क्षेत्र/राज्य प्रणाली	अप्रैल, 98 से जून, 98			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	11628	10930	698	6.0
मध्य प्रदेश	8221	7857	364	4.4
महाराष्ट्र	16771	16270	501	3.0
गोवा	364	364	0	0.0
जोड़ (प० क्षे०)	36984	35421	1563	4.2
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	10324	9156	1168	11.3
कर्नाटक	6639	5551	1088	16.4
केरल	3075	2726	348	11.3
तमिलनाडु	9919	8296	1623	16.4
जोड़ (द० क्षे०)	29957	25732	4425	14.1
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	2110	1914	196	9.3
डी० वी० सी०	1864	1954	-90	4.8
उड़िसा	2525	2555	-30	-1.2
पश्चिमी बंगाल	4018	4146	-128	-3.2
जोड़ (पू०क्षे०)	10517	10559	-42	-0.4
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
अरूणाचल प्रदेश	36.3	28.6	7.7	21.2
असम	763.0	675.2	87.8	11.5
मणिपुर	125.8	114.8	11.0	8.7
मेघालय	98.7	105.1	-6.4	6.5
मिजोरम	53.6	44.3	-9.3	17.4
नागालैंड	51.9	41.6	10.3	19.8
त्रिपुरा	132.7	127.4	5.3	4.0
जोड़ (उ० पू० क्षे०)	1262.0	113.7	125.0	9.9
अखिल भारत	112086	104308	7778	6.9

कहलगांव के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

3904. **श्री जनार्दन यादव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थर्मल पावर कहलगांव द्वारा अब तक कितने विस्थापितों का पुनर्वास किया गया;

(ख) ऐसे विस्थापित परिवारों में से कितने परिवारों के सदस्यों को नौकरी दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश परिवारों को नौकरी नहीं दी गई है जिससे भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई; और

(घ) यदि उपरोक्त तथ्य सही है तो विस्थापित परिवारों को पुनः बसाने और नौकरी उपलब्ध कराने में और कितनी समय लगेगा?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की कहलगांव सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारणवश प्रभावित परिवारों की संख्या 2062 है, जिसमें से केवल 171 परिवार वास्तविक रूप से विस्थापित हुए है। इन सभी 171 गृह विस्थापितो का इंदिरा आवास कॉलोनी में पुर्नवास किया गया है जहां प्रत्येक परिवार को 2400 वर्ग फुट के प्लॉट दिए गए हैं। 58 गृह विस्थापितों को निम्नानुसार रोजगार दिया गया है:

(1) एन०टी०पी०सी० में रोजगार 20

(2) विभिन्न करार एजेंसियों के साथ रोजगार 38

(ग) एन०टी०पी०सी० ने पुष्टि की है कि यह सच नहीं है कि परियोजना प्रभावित परिवार भोजन के अभाव में मर रहे हैं। हालांकि यह सच है कि अनेक परिवारों को रोजगार नहीं दिया गया है। क्योंकि विद्युत परियोजनाएं अनेक प्रत्यक्ष अवसर नहीं प्रदान करती है और उन्हें अप्रशिक्षित व्यक्तियों की कम आवश्यकता होती है। विद्युत परियोजनाएं फैक्ट्रियों, कृषि और व्यापार में अनुप्रवाह रोजगार अवसर उत्पन्न करती है एन०टी०पी०सी० यह सुनिश्चित करती है कि अवसर पहले उनको प्रदान किए जाएं। जिन्हें उनकी बहुत जरुरत हो। इसका ध्यान ग्राम विकास सलाहकार समिति द्वारा भी रखा जाता है जिसमें सदस्यों के तौर पर परियोजना प्रभावित परिवार एन०टी०पी०सी० और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते है।

(घ) परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में एन०टी०सी० द्वारा किए गए उपायों में उपचारात्मक कार्रवाई योजना के अंतर्गत विभिन्न आय उत्पादन स्कीमों के माध्यम से बचे हुए गृह विस्थापितों को पुनर्वास परियोजना प्रभावित परिवारों की सहकारिताओं को छोटे ठेके प्रदान करना, परियोजना परियाजना प्रभावित परिवारों को दुकानों का आवंटन और परियोजना प्रभावित की कुशलतावर्धन हेतु तकनीकी सहयोग शामिल है ताकि उनके रोजगार अवसर बढ़े और जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत उनका रोजगार सुविधाजनक हो।

Capacity Addition Target

3905. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the target set for capacity addition during the Eighth Five Year Plan (1992-97);

(b) How far this target has been realised;

(c) whether there has been major slippage in the achievement of target during the Eighth Plan;

(d) if so, the reasons therefor;

(e) the target set during the Ninth Plan (1997—2002); and

(f) the name in which the target is proposed to be realised?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) to (c) As against the capacity addition programme of 30,538 MW for the Eighth Five Plan, capacity of 16423 MW has been added through various sources. slippage in the programme has been 14115 MW.

(d) The major reasons for the gap in target and achievement are, *interalia*, paucity of funds, delay in placement of order for main plant and equipment, procedural delay in land acquisition, inter-state disputes, problems due to disturbed site conditions at some of the projects, suspension of works due to contract failures and resettlement and rehabilitation problems etc.

(e) and (f) As per the working asumption made for the Ninth Plan, a capacity addition of 40226 MW comprising of 9820 MW hydel, 16337 MW thermal, 13189 MW Gas (including liquid fuel) and 880 MW nuclear is assessed to be feasible during the period 1997-98 to 2001-02. The above capacity addition programme has